

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *169
उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026

ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाएं

*169. डॉ. भोला सिंह:
श्री धर्मबीर सिंह:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की लंबाई में हुई वृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) इसके परिणामस्वरूप ब्रॉडबैंड की गति, नेटवर्क की विश्वसनीयता और 4जी/5जी की तैयारी में कितना सुधार देखा गया है और बुलंदशहर जिले, भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में ओएफसी कनेक्टिविटी की जिला-वार स्थिति क्या है;
- (ग) महाराष्ट्र के पालघर जिले में ओएफसी की लंबाई का ब्यौरा क्या है और पालघर जिले में ब्रॉडबैंड की गति, नेटवर्क विश्वसनीयता और 4जी/5जी सेवा के खराब होने के क्या कारण हैं;
- (घ) यदि हां, तो कर्नाटक और बेंगलुरु में औसत डाउनलोड/अपलोड गति, विलंबता और नेटवर्क अपटाइम जैसे नेटवर्क निष्पादन संकेतकों के संदर्भ में क्या स्पष्ट परिणाम पाए गए हैं;
- (ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भारतनेट के अंतर्गत विस्तारित ओएफसी कनेक्टिविटी और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा शहरी क्षेत्रों में फाइबर रोलआउट से ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और डिजिटल भुगतान जैसी डिजिटल सेवाओं को व्यापक रूप से अपनाने में मदद मिली है; और
- (च) यदि हां, तो ग्रामीण-शहरी कवरेज और मुख्य अंतराल, यदि कोई हो, सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

- (क) से (च): विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

"ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाएं" के संबंध में दिनांक 11 फरवरी, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *169 के भाग (क) से (च) के संबंध में लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क): विगत तीन वित्त वर्षों (दिनांक 1.4.2022 से 31.3.2025 तक) के दौरान, 8,50,284 रूट किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाई गई थी। राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में है।

(ख) और (घ): देश भर में मापने योग्य सुधारों का विवरण इस प्रकार है:

(i) *मोबाइल ब्रॉडबैंड गति* : ऊकला के वैश्विक स्पीडटेस्ट इंडेक्स के अनुसार औसत मोबाइल ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति मार्च 2022 में 13.67 एमबीपीएस से बढ़कर दिसंबर 2025 में 132.00 एमबीपीएस हो गई है।

(ii) *नेटवर्क विश्वसनीयता*: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने 4जी/5जी नेटवर्क के लिए नेटवर्क से संबंधित मापदंडों के लिए सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) के सभी बेंचमार्क को पूरा किया।

(iii) *4जी/5जी की तैयारी*: 4जी/5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की संख्या दिनांक 31.3.2022 को 16.91 लाख से बढ़कर 31.12.2025 को 25.59 लाख हो गई, जो 51.33% की बढ़ोतरी है। राज्यवार विवरण अनुबंध-II में है।

(iv) *विलंबता*: ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2025 में विलंबता 75 मिलीसेकंड से कम है और संचयी डाउनटाइम (सेवा के लिए उपलब्ध न होने वाले सेल) 2% से कम की निर्दिष्ट सीमा के अंदर है।

ऊपर दी गई जानकारी कर्नाटक और बेंगलुरु सहित पूरे देश के लिए है।

भारतनेट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में, जिसमें बुलंदशहर जिला और भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं, ओएफसी से जुड़े और सेवा प्रदान करने के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का जिला-वार विवरण दूरसंचार विभाग की वेबसाइट (<https://www.dot.gov.in/static/uploads/2026/02/1f908efb879806628e9f32bf4b966c30.pdf>) पर उपलब्ध है।

(ग): महाराष्ट्र के पालघर जिले में, 4,830 रूट किलोमीटर ओएफसी बिछाई गई है। सड़क चौड़ीकरण कार्य, पाइपलाइन कार्य और स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक उपयोगिता कार्यों के दौरान ओएफसी कटने के कारण ब्रॉडबैंड गति और नेटवर्क विश्वसनीयता अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है।

(ड) और (च): जी, हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में ओएफसी कनेक्टिविटी के विस्तार ने देश भर में डिजिटल सेवाओं को अपनाने को काफी सुकर बनाया है। उच्च-गति ब्रॉडबैंड की उपलब्धता ने सेवा प्रदायगी और पहुंच को मजबूत किया है, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी), ऑनलाइन पोर्टलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक पहुँच मिली है। कुछ प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलों की स्थिति इस प्रकार है:

(i) आधार दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली है जो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा आधारित अद्वितीय डिजिटल पहचान प्रदान करती है। अब तक 143 करोड़ से अधिक आधार नंबर तैयार किए जा चुके हैं।

(ii) डिजिलॉकर ने आम नागरिक के लिए मूल जारीकर्ता से डिजिटल दस्तावेजों को कभी भी, कहीं भी आधार पर प्रमाणित करने के लिए पहुंच की सुविधा प्रदान की है। 65.01 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता इसकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए डिजिलॉकर पर पंजीकृत हैं।

(iii) सभी सरकारी सेवाओं के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) मोबाइल एप्लीकेशन प्रचालन में है और यह व्यक्तियों को 2,390 से अधिक सेवाएं प्रदान करता है। इसमें कुल 726.43 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं।

(iv) सीएससी, सहायता प्राप्त डिजिटल मोड में सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। दिसंबर 2025 तक देश भर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 5.87 लाख सीएससी कार्य कर रहे थे, जिनमें से 4.57 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य कर रहे थे।

(v) प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए), जिसे देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) में कार्यात्मक डिजिटल साक्षरता पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था, 6.39 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंच गया है।

(vi) वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल डिजिटल भुगतान लेनदेन 23,834 करोड़ थे। मौजूदा वित्त वर्ष में, दिनांक 4.2.2026 तक, ऐसे लेन-देन की संख्या 20,856 करोड़ है।

भारतनेट परियोजना के तहत विस्तारित ओएफसी कनेक्टिविटी के कारण 31.12.2025 तक कुल 2,14,904 ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा, देश के 6,44,131 गांवों में से (भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय के अनुसार गांव के आंकड़े), लगभग 6,34,955 गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर किया गया है, जिसमें 6,31,834 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी शामिल है। इस प्रकार, 98.09% गांवों में इंटरनेट की पहुँच है।

दिनांक 30.9.2025 तक भारत में कुल 101.78 करोड़ इंटरनेट ग्राहकों में से 42.77 करोड़ ग्रामीण ग्राहक और 59.01 करोड़ शहरी ग्राहक हैं।

दिनांक 11 फरवरी, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *169 के भाग (क) के संबंध में
अनुबंध

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	विगत तीन वित्त वर्षों (दिनांक 1.4.2022 से दिनांक 31.3.2025 तक) के दौरान बिछाई गई ओएफसी, रूट किलोमीटर में	बिछाई गई कुल ओएफसी (दिनांक 31.12.2025 तक), रूट किलोमीटर में
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	390	1,544
2	आंध्र प्रदेश	81,307	2,51,753
3	अरुणाचल प्रदेश	2,627	9,913
4	असम	27,523	93,234
5	बिहार	17,210	1,29,992
6	चंडीगढ़	2,073	24,763
7	छत्तीसगढ़	18,399	1,18,793
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	217	1,328
9	दिल्ली	10,830	77,409
10	गोवा	648	5,065
11	गुजरात	24,235	2,90,429
12	हरियाणा	8,253	83,932
13	हिमाचल प्रदेश	5,802	35,787
14	जम्मू और कश्मीर	10,809	44,479
15	झारखंड	16,720	82,034
16	कर्नाटक	27,629	2,26,763
17	केरल	88,591	2,59,252

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	विगत तीन वित्त वर्षों (दिनांक 1.4.2022 से दिनांक 31.3.2025 तक) के दौरान बिछाई गई ओएफसी, रूट किलोमीटर में	बिछाई गई कुल ओएफसी (दिनांक 31.12.2025 तक), रूट किलोमीटर में
18	लद्दाख	1,209	5,663
19	लक्षद्वीप	20	59
20	मध्य प्रदेश	30,374	2,63,453
21	महाराष्ट्र	70,178	4,06,637
22	मणिपुर	2,500	10,499
23	मेघालय	3,580	11,952
24	मिजोरम	1,718	8,332
25	नागालैंड	2,277	10,057
26	ओडिशा	26,406	1,56,298
27	पुडुचेरी	137	138
28	पंजाब	60,654	1,97,105
29	राजस्थान	45,058	2,39,458
30	सिक्किम	474	4,827
31	तमिलनाडु	1,02,865	3,08,907
32	तेलंगाना	65,691	2,37,946
33	त्रिपुरा	1,460	11,294
34	उत्तर प्रदेश	55,672	4,06,697
35	उत्तराखंड	9,428	50,178
36	पश्चिम बंगाल	27,320	1,87,364
	कुल	8,50,284	42,53,334

दिनांक 11 फरवरी, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *169 के भाग (ख) और (घ) के संबंध में अनुबंध

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक 31.3.2022 तक, 4जी/5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन	दिनांक 31.12.2025 तक, 4जी/5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन
1	अंडमान और निकोबार	399	987
2	आंध्र प्रदेश	58,722	91,588
3	अरुणाचल प्रदेश	2,595	5,060
4	असम	38,622	56,327
5	बिहार	78,755	1,26,048
6	चंडीगढ़	2,512	3,624
7	छत्तीसगढ़	32,489	49,481
8	दिल्ली	49,116	68,077
9	गोवा	3,903	5,929
10	गुजरात	1,04,209	1,57,413
11	हरियाणा	54,071	83,571
12	हिमाचल प्रदेश	17,902	27,087
13	जम्मू एवं कश्मीर	25,113	37,180
14	झारखंड	36,532	54,584
15	कर्नाटक	1,09,796	1,56,930
16	केरल	60,955	98,413
17	लद्दाख	732	1,625
18	लक्षद्वीप	14	64
19	मध्य प्रदेश	86,955	1,30,782
20	महाराष्ट्र	1,78,661	2,69,542
21	मणिपुर	5,104	7,281
22	मेघालय	5,020	6,903
23	मिजोरम	2,435	3,436
24	नागालैंड	3,596	5,205

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक 31.3.2022 तक, 4जी/5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन	दिनांक 31.12.2025 तक, 4जी/5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन
25	ओडिशा	52,082	83,767
26	पुडुचेरी	1,704	2,938
27	पंजाब	55,366	83,308
28	राजस्थान	91,620	1,42,644
29	सिक्किम	1,712	2,187
30	तमिलनाडु	1,11,698	1,72,584
31	तेलंगाना	64,864	94,612
32	त्रिपुरा	5,577	8,052
33	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1,219	1,906
34	उत्तर प्रदेश	2,13,702	3,21,123
35	उत्तराखंड	21,981	32,500
36	पश्चिम बंगाल	1,11,571	1,66,946
	कुल योग	16,91,304	25,59,704
